



THE
REMEDY
PROJECT



चीजों को ठीक करना:

टैरिफि एक्ट 1930 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी का निवारण

प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश

25 अप्रैल 2023

आभार

यह शोध रिपोर्ट द रेमेडी प्रोजेक्ट ने फ्रीडम फंड के उदार सहयोग से तैयार की गयी है। रिपोर्ट के लिए केस स्टडीज के विकास में सलाहकारों अन्ना शेर, डायना नोवोआ, लिवा श्रीधरन, मुसा न्कुना, नान्वानोक वोंगसामुथ और प्रमोद आचार्य का सहयोग रहा है।

लेखक इस रिपोर्ट के लिए गुमनाम आधार पर साक्षात्कार देने को सहमत हुए 53 कार्मिकों व अधिकारधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन नागरिक समूहों, विशेषज्ञों और अन्य भागीदारों को भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट के लिए साक्षात्कार किया गया।

अस्वीकरण

यह रिपोर्ट कि सी कंपनी द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कि सी के द्वारा बंधुआ मजदूरी कराने या कि सी प्रकार के कानूनी या मानवाधिकार उल्लंघन कि ये जाने को चिह्नित या आरोपित नहीं करती है। न ही यह कि सी भी मामले में अमेरिका की सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के निष्कर्षों की पुष्टि या समर्थन करना चाहती है। इस रिपोर्ट में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे फ्रीडम फंड या/और इस रिपोर्ट के कि सी अंशदाता के विचारों को निश्चित रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं।

1. परिचय

- 1.1 फ्रीडम फंड के सहयोग से रेमेडी प्रोजेक्ट ने 1930 के यूएस टैरिफ एक्ट के तहत बंधुआ मजदूरी का उपयोग करके बनाए गए सामानों पर 'आयात प्रतिबंध' और बंधुआ मजदूरी की स्थिति में मजदूरों व अन्य अधिकारधारकों की मदद के प्रावधानों के बीच संबंधों को समझने के लिए एक वैश्विक अध्ययन किया है। यह दस्तावेज उस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का सार प्रस्तुत करता है। पूरी अध्ययन रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त की जा सकती है।
- 1.2 1930 का यूएस टैरिफ एक्ट अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग को बंधुआ मजदूरी से बने सामान पर पूरी तरह या आंशिक रूप से आयात पाबंदी की शक्ति प्रदान करता है। टैरिफ एक्ट के अंतर्गत आयात पाबंदी इस समय कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन में बंधुआ मजदूरी के प्रति जवाबदेह बनाने का सबसे मजबूत कानूनी शस्त्र है। उनके पास बंधुआ मजदूरों का उत्पीड़न करने वालों पर सीधा आर्थिक दंड लगाने और इस उत्पीड़न से होने वाले लाभ को समाप्त करने की क्षमता है। आयात प्रतिबंध से कंपनियों पर प्रभावी वाणिज्यिक दबाव बन सकता है, ताकि वे अपनी सप्लाई चेन को बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या से मुक्त करें या फिर मूल्यवान अमेरिकी आयात बाजार खो देने के खतरे का सामना करें।
- 1.3 आयात प्रतिबंधों का एक शक्तिशाली निवारक प्रभाव भी हो सकता है। आयात प्रतिबंध के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रभाव को देखते हुए बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकार से जुड़े खतरे अब तमाम उद्योगों के प्रबंधन की बैठकों तक पहुंच गए हैं। आयात प्रतिबंध का डर या खतरा कंपनियों और उद्योगों को अपनी सप्लाई चेन में ऐसे सूचकांकों की पहचान के लिए सक्रिय कर सकते हैं और उन्हें ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रक्रियागत पहल के लिए विवश कर सकते हैं।
- 1.4 पिछले कुछ वर्षों में बंधुआ मजदूरी जितना आयात प्रतिबंधों ने कॉर्पोरेट और सरकार के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफलता पाई है। फिर भी आयात प्रतिबंधों और बंधुआ मजदूरी कर रहे लोगों की स्थितियों में सुधार के उपायों में संबंध कम स्पष्ट हैं। आयात प्रतिबंध आज भी बंधुआ मजदूरी की स्थिति में मजदूरों और अन्य अधिकार रखने वालों की स्थितियों में सुधार के एक औजार की जगह सिर्फ दंडात्मक उपाय के रूप में ही देखे जा रहे हैं। वास्तव में टैरिफ एक्ट खुद भी उपाय या उपचार का विकल्प नहीं करता है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि टैरिफ एक्ट के अंतर्गत आयात प्रतिबंध सुधार के रास्ते नहीं खोलते या नहीं खोल सकते।
- 1.5 नौ अलग-अलग केस स्टडीज के माध्यम से यह रिपोर्ट यह समझने का प्रयास करती है कि टैरिफ अधिनियम 1930 के तहत आयात प्रतिबंध किस हद तक बंधुआ मजदूरी की स्थिति में मजदूरों व अन्य अधिकारधारकों की स्थिति में सुधार करने में सफल हुए हैं। यह रिपोर्ट सुधार के तरीकों का परीक्षण करती है, श्रमिकों व अधिकारधारकों पर उनके प्रभाव का आकलन करती है और उन कारकों की पहचान करती है जो बंधुआ मजदूरी की स्थिति में श्रमिकों और अन्य अधिकारधारकों के लिए उपाय सुरक्षित करने के लिए आयात प्रतिबंधों की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं या कम करते हैं।

1 19 USC Ch.4

2 This report uses the commonly used term 'import ban' to describe the enforcement mechanism under s.307 of the Tariff Act 1930. An 'import ban' is a form of quantitative restriction which prohibits goods of a specific origin or type from entering a market. See: European Parliament (2022) [Trade-related policy options of a ban on forced labour products](#), page 10, and World Trade Organization, [Quantitative Restrictions](#)

3 Under the Tariff Act, forced labour is defined "as work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty for its nonperformance and for which the worker does not offer himself voluntarily", and includes forced or indentured child labour. See: 19 CFR § 12.42(f)

1. परिचय

व्याख्या: टैरि फ अधि नि यम 'आयात प्रति बंध' तंत्र

टैरि फ एक्ट की धारा 307 कहती है: 'दोषी श्रम या/और जबरन श्रम या/और दंडात्मक प्रति बंधों के तहत अनुबंधित श्रम द्वारा कि सी भी विदेशी देश में उत्पादित या निर्मित सभी सामान या उनके हिस्से अमेरिका के कि सी भी बंदरगाह पर प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। उनका आयात प्रति बंधित है...'

इस नियम का पालन करने के लिए अमेरिका की केंद्रीय एजेंसी सीबीपी को जिम्मा सौंपा गया है। सीबीपी कि सी शि कायत के आधार पर या स्वयं पहल कर अपने अधि कारों का प्रयोग कर सकती है।

टैरि फ एक्ट के अंतर्गत द्वि स्तरीय प्रवर्तन तंत्र काम करता है। पहले स्तर पर सीबीपी कोई शि कायत आने पर या अपनी पहल पर जांच की शुरुआत करेगी। उस जांच पर आगे बढ़ते हुए यदि सीबीपी को पता चलता है कि टैरि फ अधि नि यम की धारा 307 के अंतर्गत आने वाले सामान का प्रवेश अमेरिका में हो रहा है या उनका आयात किया जा रहा है तो सीबीपी उस सामान की नि कासी पर प्रति बंध के लिए 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' जारी करेगा। 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' अपने नाम के अनुरूप इस आदेश में बताए गए सामान को अमेरिका की बंदरगाहों से अमेरिका में प्रवेश से रोकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' सामानों को बंदरगाहों के माध्यम से अमेरिका की बाजारों में प्रवेश से रोकता है। इस सामान के आयातक, चाहे तो इसे दूसरे स्थानों तक पुनः आयात कर सकते हैं।

दूसरे स्तर पर सीबीपी धारा 307 के तहत सवालों के घेरे में सामान के बारे में वि त्त सचि व की अनुशंसा से एक सूचना प्रकाशित करेगा। इस सूचना के घेरे में आए सामान का कि सी भी अमेरिका की बंदरगाह में प्रवेश नि षि द्ध हो जाएगा, अमेरिका में उनका आयात प्रति बंधित हो जाएगा और अमेरिका की बंदरगाहों में ऐसे सामान को जब्त किया जा सकेगा। अधि कांश मामलों में सीबीपी सूचना प्रकाशित नहीं करता है। फरवरी 2023 तक 53 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' जारी किए गए थे, कि न्तु सि र्फ नौ सूचनाएं प्रकाशित हुई थीं।

सीबीपी के पास ऐसे आयातकों पर अर्थदंड लगाने के अधि कार हैं जो 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन में शामिल होने के बावजूद नियमवि रूद्ध सामग्री अमेरिका में लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं। डि संबर 2022 तक सीबीपी ने 'वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर' या सूचना प्रकाशन में शामिल सामान का आयात करने वाले सि र्फ एक आयातक के खिलाफ अर्थदंड लगाया है।

4 19 USC 4 §1307

5 19 CFR § 12.42

6 19 CFR § 12.42(a) and (b)

7 19 CFR § 12.42(e)

8 19 CFR § 12.42(e)

9 19 CFR § 12.42(f)

10 19 CFR § 12.42(f); 19 CFR § 12.42(f)

11 CBP, [Withhold Release Orders and Findings List](#)

12 CBP (13 August 2022) [CBP Collects \\$575,000 from Pure Circle U.S.A. for Stevia Imports Made with Forced Labor](#)

1. परिचय

‘उपाय तक पहुंच’ बनाम ‘उपचार’

‘उपाय’ या ‘उपाय तक पहुंच’ क्या है?

व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत ‘उपाय’ उन लोगों के लिए ठोस उपचार के प्रावधान को संदर्भित करता है जिन्हें न के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है ताकि उस नुकसान को ठीक करने में मदद मिल सके।

यह दोनों को संदर्भित करता है: (अ) प्रति कूल मानवाधिकार प्रभाव के लिए उपचार प्रदान करने की प्रक्रियाएँ और (ब) मूल परिणाम जो प्रति कूल प्रभाव का प्रति कार कर सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं। ये परिणाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माफी, बहाली, पुनर्वास, वितीय या गैर-वितीय मुआवजा, और दंडात्मक प्रतिबंध (चाहे आपराधिक या प्रशासनिक, जैसे जुर्माना), साथ ही निषेधाज्ञा या दोबारा ऐसा न होने की गारंटी के साथ नुकसान की रोकथाम करना।

टैरिफ एक्ट 1930 के तहत उपचार

‘उपचार’ भी सीबीपी द्वारा टैरिफ अधिकार नियम की धारा 307 के तहत आयात प्रतिबंध को ‘उठाने’ के बारे में निर्णय लेने के संदर्भ में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है। इस संदर्भ में प्रयोग करते समय, इसका अर्थ ऊपर लिखी संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों की परिभाषा से अलग है।

सीबीपी ‘वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर’ या सूचना प्रकाशन सिर्फ दो तरीकों, संशोधन और रद्द करके हटा सकता है। संशोधन ‘वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर’ या सूचना प्रकाशन का आंशिक या पूर्ण निबन्धन होता है, वहीं रद्द करना ‘वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर’ या सूचना प्रकाशन को पूरी तरह हटा लेना होता है।

अपने निदेश दस्तावेजों में सीबीपी का कहना है कि वह ‘वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर’ को तब तक संशोधित या रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक बंधुआ मजदूरी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। फिर भी, ये निदेश दस्तावेज विशेष रूप से उपचार को परिभाषित नहीं करते हैं। ‘उपचार’ शब्द का उपयोग टैरिफ अधिकार नियम या इससे जुड़े संघीय विनियमों में भी नहीं किया गया है। सामान्य रूप से, सीबीपी उपचार शब्द का प्रयोग बंधुआ मजदूरी के संकेतों को दूर करने की प्रक्रिया के रूप में करता है (विशेषकर, बंधुआ मजदूरी के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतों के लिए), न कि प्रभावित अधिकारधारकों के लिए उपायों के प्रावधान के रूप में। यद्यपि ये दोनों विचार एक जैसे हैं, किन्तु ये एक नहीं हैं।

इन दोनों विचारों में अंतर समझने के लिए शब्द ‘उपाय’ का प्रयोग ऊपर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने में किया गया है, वहीं शब्द ‘उपचार’ का प्रयोग सीबीपी की समाधान प्रक्रिया (यानी बंधुआ मजदूरी के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संकेतकों की समाप्ति) के रूप में किया गया है।

- 13 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2012) *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide*, page 7
- 14 See: CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*
- 15 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*; ILO (1 October 2012) *ILO Indicators of Forced Labour*
- 16 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*; CBP (October 2021) *How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?*
- 17 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*

2. कार्यप्रणाली

- 2.1 रिपोर्ट टैरिफ अधिनि यम के तहत आयात प्रतिबंधों और श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों के लिए उपचार के प्रावधान के बीच संबंधों की जांच करती है। इसमें शामिल है:
- टैरिफ अधिनि यम के तहत 'उपचार' की अवधारणा को कैसे समझा और लागू किया गया है?
 - जहां एक कंपनी एक आयात प्रतिबंध के अधीन है, कंपनी और अन्य जिम्मेदार लोगों ने प्रतिबंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दों के निस्तारण के लिए क्या उपाय किए हैं?
 - उन उपायों ने किस हद तक बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों की स्थिति में सुधार की दिशा तय की है? सुधार के क्या उपाय किए गए और उनका क्या प्रभाव पड़ा?
 - बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए कौन से कारक आयात प्रतिबंधों की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं या कम करते हैं?
- 2.2 रिपोर्ट इन मुद्दों पर उन मामलों के नौ केस स्टडीज के माध्यम से विचार करती है जहां एक कंपनी ने टैरिफ अधिनि यम के तहत लगाए गए बंधुआ मजदूरी आयात प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। इन केस स्टडीज को आयात प्रतिबंधों से सीधे प्रभावित कंपनियों और उद्योगों में कार्यरत 53 श्रमिकों के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसायटी समूहों और दुनिया भर के स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से विकसित किया गया है। उसके साथ मौके पर जाकर जांच-पड़ताल और आंकड़ों पर केंद्रित शोध भी किया गया है।

केस स्टडीज का सारांश

कार्यक्षेत्र	उद्योग	इकाइयां या उद्योग
ब्राजील	बोन ब्लैक/ बोन चार	बोनेचार कारवाओ एटि वदो डो ब्राजील लि मि टेड (बोनचार)
भारत	गारमेंट्स	नाची एपेरल्स प्राइवेट लि मि टेड
मलेशिया	पॉम आयल	एफजीवी होल्डिंग्स बीएचडी
मलेशिया	पॉम आयल	साइम डार्बी प्लांटेशन बीएचडी
मलेशिया	डि स्पोर्ट्स दस्ताने	टॉप ग्लोव कॉर्पोरेशन बीएचडी
मलावी	तम्बाकू	मलावी में उत्पादित तम्बाकू और मलावी में उत्पादित तम्बाकू युक्त उत्पाद
नेपाल	कालीन, हाथ से बुने हुए ऊनी उत्पाद	कुमार कारपेट, सिघं कारपेट प्राइवेट लि मि टेड, नोरसांग कारपेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि मि टेड, अन्नपूर्णा कारपेट, एवरेस्ट कारपेट, वैली कारपेट, और केके कारपेट इंडस्ट्रीज काठमांडू
मछली पकड़ने की नाव: डा वांग	दूरस्थ जल में मछली पकड़ना	फिशिंग वेसेल: डा वांग
थाईलैंड	मछली पकड़ने के जाल	खोन कीन फिशिंग नेट फैक्ट्री कंपनी लि मि टेड डके पापै क फिशिंग नेट फैक्ट्री लि मि टेड

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

A. टैरिफ अधिनि यम तंत्र के तहत 'उपचार' की अवधारणा को कैसे समझा और लागू किया गया है?

टैरिफ अधिनि यम के संदर्भ में, 'उपचार' का तात्पर्य बंधुआ मजदूरी की स्थितियों में लोगों के लिए ठोस उपचार के प्रावधान के बजाय, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने से है।

- 3.1 सीबीपी 'उपचार' शब्द का उपयोग तब करता है जब वह वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को हटाना या निष्कर्षों को बदलने के बारे में निर्णय लेता है। वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या निष्कर्ष दो में से एक तरीके से उठाए या बदले जा सकते हैं:
- 'संशोधन' वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या निष्कर्ष को लागू करने के फैसले का आंशिक या पूर्ण निलंबन है। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियों या उत्पादों को इसके दायरे से बाहर करने के लिए एक वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को संशोधित किया जा सकता है।
 - 'निरसन' सीबीपी द्वारा इस निर्धारण के आधार वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर या निष्कर्ष को पूरी तरह समाप्त करना है, कि उक्त संस्था या उससे जुड़े लोग बंधुआ मजदूरी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं।
- 3.2 अपने मार्गदर्शक दस्तावेजों में, सीबीपी कहता है कि यह वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर को तब तक संशोधित या रद्द नहीं करेगा, जब तक कि सभी बंधुआ मजदूरी संकेतकों को दूर नहीं किया जाता है।" हालांकि, ये मार्गदर्शक दस्तावेज विशेष रूप से 'उपचार' को परिभाषित नहीं करते हैं। 'उपचार' शब्द का उपयोग टैरिफ अधिनि यम या इसके साथ जुड़े संघीय विनियमों में भी नहीं किया गया है।
- 3.3 व्यवहार में, सीबीपी 'उपचार' शब्द का उपयोग अधिकांश धारकों के जीवन में सुधार के प्रावधानों के बजाय बंधुआ मजदूरी के संकेतकों (विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतकों) को हटाने की प्रक्रिया के रूप में करता है। यद्यपि दोनों अवधारणाएं एक जैसी हैं, किन्तु वे समान नहीं हैं।
- 3.4 उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में जांचे गए कई मामलों के अध्ययन में, ऋण बंधन (उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिकों द्वारा भर्ती शुल्क के भुगतान से उत्पन्न), सीबीपी द्वारा चिह्नित बंधुआ मजदूरी का एक प्रमुख संकेतक था। जवाब में, कुछ कंपनियों ने बंधुआ मजदूरी के इस संकेतक को 'उपचारित' करने (यानी हटाने) के लिए प्रवासी श्रमिकों से लिए गए भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति की। भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति श्रमिकों को ऋण बंधन की संभावित स्थितियों से हटाकर बंधुआ मजदूरी के संकेतकों के 'निवारण' (अर्थात्, हटाने) में मदद कर सकती है। हालांकि, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति उन श्रमिकों को मुआवजे की पेशकश करने के समान नहीं है, जिन्हें ऋण बंधन के माध्यम से बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया गया था।

18 See: CBP (March 2021) [Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview](#); CBP (October 2021) [How are WRO and/or finding modifications and revocations processed?](#)

19 Ibid.

20 Ibid.

21 CBP (March 2021) [Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview](#)

22 In some cases, migrant workers interviewed for the Report reported that the recruitment fee reimbursement payment they received was slightly more than the actual recruitment fee that they paid. This surplus may be considered to have some compensatory value for workers, but it is not the same as a payment that is specifically intended to compensate workers for having been subjected to conditions of forced labour.

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

3.5 इसके अलावा, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों का समाधान हमेशा व्यक्तिगत समाधान की ओर नहीं ले जाता है। उदाहरण के लिए 2020 में सीबीपी ने "सामाजिक अनुपालन कार्यक्रमों और उसकी आपूर्ति श्रृंखला से बंधुआ मजदूरों के जोखिम को कम करने के प्रयासों" के मल्टी-यांकन के आधार पर मलावी में दो तंबाकू कंपनियों पर लागू विदहोल्ड रिजिस्ट्रेशन ऑर्डर को संशोधित किया था। फिर भी, रिपोर्ट में जिन तंबाकू श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया, उन्होंने बताया कि आयात प्रतिबंधों के जवाब में श्रमिकों को कोई सुविधाएं नहीं प्रदान की गईं।

यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि जबरन बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को पर्याप्त रूप से समाप्त मानने के लिए सीबीपी कौन सा प्रमाणिक मानक लागू करता है।

- 3.6 ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीपी ने अलग-अलग मामलों में यह तय करने के लिए अलग-अलग मानक अपनाए हैं कि सी कंपनी ने बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को पर्याप्त रूप से सुधारा है यानी समाप्त कर दिया है।
- 3.7 तीन फरवरी 2023 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सीबीपी ने कहा कि वह रिजिस्ट्रेशन ऑर्डर या निष्कर्षों को तब तक संशोधित नहीं करता है जब तक कि एजेंसी के पास संबंधित सामग्री का निर्माण बंधुआ मजदूरी से न होने का सबूत न हो? हालांकि, यह हमेशा इस मानक को लागू करता दिखता नहीं है।
- 3.8 विशेष रूप से, नवंबर 2019 में, सीबीपी ने बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम का प्रयोग कर तंबाकू उत्पादन की चिंतना के कारण मलावी से तंबाकू के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जून और अगस्त 2020 में, सीबीपी ने बंधुआ मजदूरी के जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के प्रयासों के आधार पर मलावी की दो सबसे बड़ी तंबाकू पत्ती खरीदने वाली कंपनियों पर लगे आयात प्रतिबंध को संशोधित किया। सीबीपी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने अपने खेतों से तंबाकू उत्पादन में बंधुआ मजदूरी का प्रयोग न करने का दावा किया था और इसके समर्थन में पर्याप्त तथ्य भी प्रस्तुत किए थे।
- 3.9 मलावी से तंबाकू के आयात पर प्रतिबंध को संशोधित करने के लिए सीबीपी के निर्णय अन्य मामलों की तुलना में अलग मानक को अपनाते हुए प्रतीत होते हैं। मलावी के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीपी ने एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अंतर्गत सिर्फ इस आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि कंपनियां बंधुआ मजदूरी के जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के प्रयासों को प्रदर्शित करें।

23 CBP (3 June 2020) [CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi](#)

24 CBP (3 February 2023) [CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia](#)

25 CBP (1 August 2020) [CBP Modifies Withhold Release Order on Tobacco Imports from Limbe Leaf Tobacco Company Ltd. in Malawi](#)

26 CBP (3 June 2020) [CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi](#)

27 CBP (3 February 2023) [CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia](#)

28 CBP (3 February 2023) [CBP Modifies Finding on Sime Darby Plantation Berhad in Malaysia](#)

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

B. जहां कोई कंपनी आयात प्रतिबंध के अधीन है, तो प्रतिबंधों के जवाब में कंपनी और अन्य जिम्मेदार लोगों ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दों को हल करने के क्या उपाय किए हैं?

कुछ मामलों में आयात प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी, नीतिगत व परिचालन स्तर पर बदलाव का कारण बने हैं।

- 3.10 टैरिफ अधिनियम के तहत आयात प्रतिबंधों का व्यापक प्रभाव पड़ा है, और वे अक्सर सुधार की राह में बाधक उद्योगों में तेजी से बदलाव लाने के लिए उत्प्रेरक रहे हैं।
- 3.11 वास्तविक या धमकी भरे आयात प्रतिबंधों के जवाब में, मलेशिया में रबड़ के दस्ताने और ताड़ के तेल उद्योगों में कंपनियों ने लगभग 82,000 प्रवासी श्रमिकों को भर्ती शुल्क के एवज में 115.4 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक चुकाने के लिए मजबूर किया है। रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एलायंस जैसी नई कॉर्पोरेट स्थिरता पहल शुरू की गई हैं, कर्मचारी शिकायत तंत्र को मजबूत किया गया है, और भर्ती, कॉर्पोरेट प्रशासन और स्थिरता नीतियों में सुधार किया गया है।



3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

प्रवासी श्रमि कों द्वारा भुगतान की गई भर्ती फीस वापसी के लि ए मलेशि याई पॉम आयल और दस्ताना नि र्मा ण कं पनि यों की प्रति बद्धताएं

कंपनी	भुगतान कि या गया/ वादा कि या गया (औसतन)	श्रमि कों की संख्या
सि म डारबी	18.2 मि लि यन अमेरि की डॉलर	34,000
टॉप ग्लोव	33.3 मि लि यन अमेरि की डॉलर	13,000
कोस्सान ग्रुप	11.2 मि लि यन अमेरि की डॉलर	5,500
हर्टा ल्जि या	9.1 मि लि यन अमेरि की डॉलर	अघोषि त
सुपरमैक्स	5.1 मि लि यन अमेरि की डॉलर	1,750
ब्राइटवे	8.4 मि लि यन अमेरि की डॉलर	2,719
डब्ल्यूआरपी	4.7 मि लि यन अमेरि की डॉलर	1,600
एफजीवी	24.9 मि लि यन अमेरि की डॉलर	23,333 + पूर्व श्रमि क
कुल	115.4 मि लि यन अमेरि की डॉलर	81,902

3.12 सीबीपी की छापामार कार्रवाइयों से कानूनी कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है। आयात प्रति बंधों के क्रम में आगे बढ़ते हुए अमेरि का और इंग्लैंड में उन कं पनि यों के खि लाफ सि वि ल मुकदमे कि ए गए हैं, जि न्होंने आयात प्रति बंध के दायरे में आई कं पनि यों के उत्पादों को प्राप्त कि या है या उनसे लाभ कमाया है। ताइवान में, एक आयात प्रति बंध के चलते मछली पकड़ने वाले जलयान दा वांग पर तस्करी और बंधुआ मजदूरी के तहत मुकदमा कायम कराया गया और इस जलयान का लाइसेंस रद्द कर दि या गया।

- 30 Sime Darby Plantation Bhd (15 February 2022) [Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations](#); Sime Darby Plantation Bhd (21 April 2022) [Annual Integrated Report 2021](#), page 148; Sime Darby Plantation Bhd (29 April 2022) [Sustainability Report 2021](#), page 41
- 31 Top Glove [Continuous Improvement Report](#)
- 32 Kossan Group (10 June 2021) [Kossan Group Remediation Program](#); The Diplomat (14 September 2021) [Debt Bondage Payouts Flow to Workers in Malaysia's Glove Industry](#)
- 33 Hartalega Holdings Bhd (8 June 2021) [Hartalega Completes Remediation of Recruitment Fees Totalling RM 41 million](#)
- 34 The Diplomat (14 September 2021) [Debt Bondage Payouts Flow to Workers in Malaysia's Glove Industry](#)
- 35 Reuters (19 May 2021) [An audit gave the all-clear. Others alleged slavery](#)
- 36 FMT (8 July 2020) [Glovemaker WRP to reimburse recruitment fee paid by workers](#)
- 37 FGV (27 February 2023) [FGV's FY2022 Financial Performance Charts New Record Since Listing](#)
- 38 For example, in 2021 CBP imposed a WRO on Malaysian glovemaker Brightway Group over alleged forced labour at the company. In 2022, a civil lawsuit was filed in the United States under the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act against health and safety equipment company Ansell and personal care company Kimberly-Clark over the companies' alleged ties to Brightway. See: Ansell (11 August 2022) [TVPRALawsuit Against Ansell](#) ; International Rights Advocates, [Cases: Kimberly Clark and Ansell](#)
- 39 Kaohsiung District Prosecutors' Office (17 May 2022) [Kaohsiung District Prosecutors' Office Charged 9 People for Exploiting and Abusing Foreign Crew on A Longline Fishing Boat, "Da Wang", Against Human Trafficking Prevention Act](#)

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

- 3.13 आयात प्रतिबंधों ने न्यायिक व नीतिगत बदलावों की राह भी खोली है। ताइवान में, आयात प्रतिबंधों ने मत्स्य पालन और मानवाधिकारों के लिए एक आधिकारिक कार्य योजना को अपनाने में मदद की, जिसमें दूर जाकर मछली पकड़ने वाले श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन में 100 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि शामिल है।
- 3.14 थाइलैंड में आयात प्रतिबंध की धमकी के चलते थाइलैंड की शाही सरकार ने जेल श्रम का प्रयोग करते हुए मछली पकड़ने के जालों का निर्माण बंद करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। यह कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी को रोकने के मामले में प्रभावी तरीके का उदाहरण साबित हो सकता है।
- 3.15 मलेशिया में सरकार ने दस्ताना निर्माताओं और पॉम ऑयल कंपनियों के खिलाफ आयात प्रतिबंधों की एक श्रृंखला के बाद श्रम कानूनों और नीतियों में कई सुधार पेश किए हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा, और बंधुआ मजदूरी को अपराध के दायरे में लाने की पहल शामिल है। हालांकि इन सभी सुधारों को आयात प्रतिबंधों के प्रभाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय देना संभव नहीं है। हां, आयात प्रतिबंधों को इन सुधारों को और अधिक तेजी से अपनाने के लिए प्रेरक माना जा सकता है।
- 3.16 अधिक व्यापक रूप से, हितधारकों का मानना है कि सीबीपी प्रवर्तन कार्रवाइयां उन तरीकों में बदलाव ला रही हैं जिन्हें ससेकंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में बंधुआ मजदूरी तक पहुंच बना रही हैं - यहां तक कि उन कंपनियों में भी जो आयात प्रतिबंधों से सीधे प्रभावित नहीं हैं। उनका मानना है कि आयात प्रतिबंध सामाजिक अनुपालन में भारी बदलाव ला रहे हैं क्योंकि बड़े व्यावसायिक निहितार्थों के बारे में... चार साल पहले भी मानक अभ्यास के रूप में जो स्वीकार्य था, वह अब अच्छा अभ्यास नहीं है।
- 3.17 कुछ मामलों में, आयात प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में बंधुआ मजदूरी को प्रबंधन स्तर तक पहुंचा दिया, जिसे वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। उदाहरण के लिए, डब्ल्यूआरओ के जवाब में, मलेशियाई पाम ऑयल कंपनी सिम डारबी प्लांटेशन ने जुलाई 2021 में बंधुआ मजदूरी के उपचार की निगरानी और निगरानी के लिए एक बोर्ड सस्टेनेबिलिटी कमिटी की स्थापना की, और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर इसके प्रदर्शन को ट्रैक करने और मापने के लिए नया आंतरिक ईएसजी स्कोरकार्ड पेश किया।
- 3.18 अन्य मामलों में, काम की परिस्थितियों में सुधार, कंपनी की नीतियों और प्रथाओं को बदलने, या कानूनी और नीतिगत सुधार लाने के संदर्भ में आयात प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। यह मलावी और नेपाल के मामलों में उल्लेखनीय था - जहां हितधारकों ने आम तौर पर यह रिपोर्ट नहीं दी थी कि आयात प्रतिबंध काम की परिस्थितियों, कंपनी प्रथाओं, या राष्ट्रीय कानूनी और नीतिगत परिदृश्य में बंधुआ मजदूरी से निपटने के मुख्य हथियार बने।

40 Council of Agriculture (May 2022) [Action Plan for Fisheries and Human Rights](#)

41 Department of Corrections (1 March 2021) [Corrections reforms prisoners' labour according to human rights standards](#)

42 Employment (Amendment) Act 2023

43 Interview with Jen Jahnke, Associate Director, Impactt Limited

44 Sime Darby Plantation (15 February 2022) [Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations](#); Sime Darby Plantation Bhd (21 March 2022) [Update session: Ban \(Finding\) issued by the United States](#)

45 [Customs and Border Protection on Sime Darby Plantation](#), page 24; Sime Darby Plantation (15 February 2022) [Sime Darby Plantation Institutes Sweeping Changes in Governance and Operations](#)

45 This does not mean that there have been no such reforms or improvements. Rather, there was no clear evidence that any such reforms and improvements were directly attributable to the impact of an import ban.

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

C. उन उपायों ने कि स हद तक बंधुआ मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों की स्थिति में सुधार के प्रावधान सुनिश्चित कराए हैं? क्या सुधार हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा?

आयात प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरों के शिकारियों के लिए महत्वपूर्ण उपायों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें समेकित कंपनियों द्वारा मलेशिया में लगभग 82,000 प्रवासी श्रमिकों को भर्ती शुल्क के रूप में 115.4 मिलियन अमरीकी डालर चुकाने की प्रतिबद्धता शामिल है। लेकिन भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा, समस्या के सीधे समाधान के लिए कुछ अन्य प्रयास भी किए गए हैं।

- 3.19 रिपोर्ट ने आयात प्रतिबंधों के जवाब में श्रमिकों और प्रभावित अधिकारधारकों को समस्या से मुक्ति के लिए की गई कोशिशों को जानने की पड़ताल की। नीचे दी गई तालिका का जांचे गए प्रत्येक मामले के अध्ययन में पहचाने गए विभिन्न प्रयासों को दर्शाती है।
- 3.20 तालिका उन उदाहरणों पर प्रकाश डालती है जहां यह इंगित करने वाले साक्ष्य थे कि श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों को एक उपाय प्रदान किया गया था। तालिका यह इंगित नहीं करती है कि क्या वे उपाय प्रभावी थे या प्राप्तकर्ताओं के दृष्टिकोण से पर्याप्त थे, क्योंकि यह हर मामले में सत्यापित करना संभव नहीं था।
- 3.21 नीचे दी गई तालिका को संकलित करने के लिए सूचना के कई स्रोतों का उपयोग किया गया था। जहां संभव हुआ, वहां साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत स्वयं प्रभावित श्रमिकों और अधिकारधारकों के साक्षात्कार थे। ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी की घोषणाएं और प्रकाशन और स्वतंत्र मीडिया कवरेज जैसे दूसरे स्रोतों से इनकी पुष्टि की गयी। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्रोतों द्वारा जुटाई गई जानकारी को अलग करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग किया गया है।
- (a) हरे रंग से उन प्रयासों को दर्शाया गया है, जिन्हें उनके बारे में साक्षात्कार के दौरान श्रमिकों और अधिकारधारकों ने बताया था कि उन्हें उन प्रयासों का लाभ प्राप्त हुआ था।
 - (b) पीले रंग में उन उपायों की जानकारी दी गयी है, जिन्हें नकारा जाया कि कंपनी या सरकारों ने प्रेस विज्ञापनों, विभिन्न प्रकाशनों या ऑडिट रिपोर्ट में किया गया था, कि न तो साक्षात्कारों में उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसा कर्मचारियों के साक्षात्कार न हो सकने या जिन्हें कर्मचारियों के साक्षात्कार हुए, उनके द्वारा टिप्पणी करने से इनकार करने के कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि जिन्हें लोगों का साक्षात्कार हुआ, वे उपाय की जानकारी के समय उस कंपनी या उद्योग में काम नहीं कर रहे थे।
 - (c) ग्रे रंग से उन उपायों को दिखाया गया है, जिन्हें उनके बारे में कंपनी या सरकारों ने तो उपाय कि वे जाने की जानकारी दी थी, कि न तो श्रमिकों ने साक्षात्कार के दौरान उनकी पुष्टि नहीं की थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी या सरकारों द्वारा दी गयी जानकारी और श्रमिकों के बयानों में उपायों को लेकर विसंगति थी।

46 The list of remedies is derived from the forms of remedy that were observed to have been provided in the different case studies, as well as the OHCHR interpretive guide to the UNGPs. See: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2012) *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide*, page 7

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

आयात प्रतिबंधों के जवाब में कि ए गए उपायों का सारांश

हरा: स्वयं बताया गए उपाय, और रिपोर्ट के लिए आयोजित कार्यकर्ता साक्षात्कारों में पुष्टि की गई।

ऑरेंज: स्वयं बताया गए उपाय और रिपोर्ट के लिए आयोजित कार्यकर्ता साक्षात्कारों द्वारा पुष्टि नहीं की गई।

Yellow: स्वयं बताया गए उपाय और रिपोर्ट के लिए श्रमिकों के साक्षात्कार करना संभव नहीं हो सका।

स्थिति	वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/निष्कर्षों में संशोधन/समापन				वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/निष्कर्षों में संशोधन/समापन न होना		वि दहोल्ड रि लीज ऑर्डर/निष्कर्ष न होना
केस स्टडी	मलेशिया या रबर ग्लोव्स (टाप ग्लोव)	मलावी टुबैको	नेपाल कारपेट्स (अन्नपूर्णा कारपेट)	मलेशिया या पॉम आयल (साइम डार्बी)	मलेशिया या पॉम आयल (एफजीवी होल्डिंग्स)	डिस्टेंस वाटर फिशिंग (द डा वांग)	थाइलैंड फिशिंग नेट्स

क्षमायाचना							
मुआवजा / क्षति पूर्ति	Yellow						
पुनर्वास							
भर्ती शुल्क प्रति पूर्ति	Yellow			Green	Yellow		
दोहराव न होने की गारंटी							
रहन-सहन व काम की स्थितियों में सुधार	Yellow		Yellow	Green	Blue	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं
सेवायोजन / रोजगार नीतियों में सुधार	Yellow		Yellow	Blue	Blue	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं	सरकारी सुधारों के माध्यम से, कंपनी द्वारा उपाय नहीं
अपराधियों के लिए कानूनी जवाबदेही						Green	
बेहतर शिफ्ट कायत चैनल	Yellow		Yellow	Green	Blue		

*Worker interviews not conducted for the purpose of this report

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

3.22 जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

- (a) एक मामले में, रिपोर्ट ने स्पष्ट सबूत की पहचान नहीं की कि सुधार के उपाय किए गए थे या आयात प्रतिबंध के जवाब में व्यक्तिगत अधिकारधारकों को उपचार प्रदान किया गया था।
- (b) चार मामलों में, इस बात के सबूत थे कि आयात प्रतिबंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने के लिए कंपनीयों द्वारा सुधार किया गया था। इसमें कंपनी की नीतियों और प्रशासन प्रणालियों में सुधार के माध्यम से, बेहतर कर्मचारी आवास में निवेश करना शामिल है। लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि उन प्रयासों के तहत व्यक्तिगत अधिकारधारकों को उपचार प्रदान किया गया था।
- (c) दो मामलों में, इस बात के प्रमाण मिले थे कि आयात प्रतिबंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने के लिए संबंधित कंपनीयों द्वारा सुधार किया गया था, और उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत अधिकारधारकों को सुविधाएं प्रदान की गई थीं। दोनों मामलों में, भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यक्तिगत लाभ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, इनमें से एक मामले में, बंधुआ मजदूरी की स्थिति में रहने वाले श्रमिकों के लिए मुआवजे के रूप में व्यक्तिगत उपाय की पेशकश की गई थी।

3.23 मलेशिया में प्रवासी श्रमिकों को भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा, प्रभावित अधिकारधारकों के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय भी किए गए। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट ने केवल एक उदाहरण की पहचान की जिसमें एक कंपनी सार्वजनिक रूप से उन श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध थी जो बंधुआ मजदूरी की स्थिति में थे।

3.24 बहुत से मामलों में, कंपनीयों ने अपने प्रबंधन, मानवाधिकारों, भर्ती, और रोजगार नीतियों व प्रथाओं में परिवर्तन करके आयात प्रतिबंधों का जवाब दिया है। ये नीतिगत परिवर्तन भविष्योन्मुखी व भावी उपाय का एक रूप हो सकते हैं - जिसमें वे यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भविष्य में श्रमिकों को नुकसान के समान रूपों का अनुभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए, कंपनीयों ने कथित तौर पर अपनी भर्ती और रोजगार नीतियों और प्रथाओं (सात में से पांच केस स्टडीज) में सुधार पेश किए हैं, और कर्मचारी शिकायत तंत्र को मजबूत किया है (सात केस स्टडीज में से चार)।

3.25 हालांकि, जिन नीतिगत सुधारों का वादा किया गया था, उन श्रमिकों की दशा व अनुभवों में उन सुधारों का असर नहीं दिखा, जिनसे इस रिपोर्ट के लिए बात की गई थी। कम से कम तीन मामलों के अध्ययन में, कंपनीयों द्वारा प्रदान किए गए उपायों और रिपोर्ट के लिए साक्षात्कार किए गए श्रमिकों के अनुभवों के बीच एक विसंगति की पहचान की गई थी।

जिन केस स्टडीज का परीक्षण किया गया, उनमें आयात प्रतिबंध आम तौर पर श्रमिकों के लिए नौकरी के नुकसान या अन्य प्रतिफल आर्थिक प्रभावों का परिणाम नहीं थे

48 Tobacco, Malawi

49 Palm oil, Malaysia (FGV Holdings), carpets, Nepal (Annapurna Carpet), distant water fishing (the *Da Wang*), Thailand, fishing nets

50 Malaysia, palm oil (Sime Darby), Malaysia, rubber gloves (Top Glove). In some cases, migrant workers interviewed for this report reported that the recruitment fee reimbursement payment they received was slightly more than the actual recruitment fee that they paid. This surplus may be considered to have some compensatory value for workers, but it is not the same as a payment that is specifically intended to compensate workers for having been subjected to conditions of forced labour.

51 Malaysia, rubber gloves (Top Glove)

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

- 3.26 पर्यवेक्षकों ने महसूस की कि या है कि आयात प्रतिबंधों से प्रभावित कंपनियों और उद्योगों में श्रमिकों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना हो सकती है (उदाहरण के लिए, ऑर्डर कम होने या कारखाने बंद होने के कारण)। आयात प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को उन कंपनियों या उद्योगों से अलग होने या उनसे अलग होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो उस उद्योग या कंपनी में बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लिए काम करने के बजाय बंधुआ मजदूरी का उच्च जोखिम उठाते हैं। रिपोर्ट में जिन केस स्टडीज का परीक्षण हुआ, उनमें ऐसे खतरे सामने नहीं आए।
- 3.27 केस स्टडीज के परीक्षण के दौरान, रिपोर्ट में आयात प्रतिबंधों के कारण श्रमिकों की नौकरी जाने, मजदूरी में कमी या अन्य प्रतिफल प्रभावों का प्रमाण नहीं मिला। वास्तव में, कुछ मामलों में, आयात प्रतिबंधों से प्रभावित कंपनियों के टर्नओवर या लाभ में कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं दिखाई दी (हालांकि इन कंपनियों ने अन्य प्रतिफल वाणिज्यिक और प्रतिष्ठित प्रभावों का अनुभव किया)। यह विशेष रूप से बड़ी कंपनियों के मामले में था।
- 3.28 दो केस स्टडीज (भारत की मैनेची अपैरल्स और ब्राजील की बोनुचर) में आयात प्रतिबंधों ने प्रभावित कंपनियों में संभावित नौकरी के नुकसान के जोखिम को जन्म दिया। हालांकि, दोनों ही मामलों में, आयात प्रतिबंधों को जल्दी से संशोधित किया गया और उन संभावित प्रतिफल प्रभावों के अमल में आने से पहले हटा लिया गया। उदाहरण के लिए, मैनेची अपैरल्स के मामले में, सीबीपी ने नागरिक समाज समूहों और ट्रेड यूनियनों द्वारा यह चिंतित किया जा रहा था कि डब्ल्यूआरओ डिडिंग ग्लोव समझौते के सफल कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकता है, केवल छह सप्ताह के भीतर डब्ल्यूआरओ को संशोधित किया गया। साथ ही एक ऐसा समझौता सामने आया, जिसमें कंपनी के भीतर लिगिंग या जाति आधारित हिंसा व उत्पीड़न की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान निकाला गया।
- 3.29 प्रतिफल परिणामों की संभावना का मतलब यह नहीं है कि आयात प्रतिबंधों को बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न ही इसका मतलब यह है कि आयात प्रतिबंध लगाने के लिए साक्ष्य सीमा बढ़ा दी जानी चाहिए। हालांकि, प्रतिफल प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना आयात प्रतिबंध लगाने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में श्रमिकों, अधिकारधारकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।



- 52 Anti-Slavery International (June 2021) [Anti-Slavery International and European Center for Constitutional and Human Rights' position on import controls to address forced labour in supply chains](#), page 4; Corporate Accountability Lab (August 2020) [Using the Master's Tools to Dismantle the Master's House: 307 Petitions as a Human Rights Tool](#)
- 53 It is possible that the companies' revenues or profits may have been higher but for the import ban – but this was not possible to quantify this within the scope of this study. It was also not possible to assess, within the scope of this study, why there was no reduction in turnover or profits. For example, the affected companies may have been able to find alternative export destinations for their products outside of the United States. In other cases, companies experienced significant increases in sales as a result of the COVID-19 pandemic (e.g., rubber glove makers) which may have offset the effects of the import ban.
- 54 Who can be considered credible representatives of workers will depend on the circumstances. They may include trade unions, but in some contexts workers (and especially migrant workers) may be prevented from forming or leading trade unions. In those circumstances, other forms of credible worker representation may be appropriate.
- 55 Anti-Slavery International (June 2021) [Anti-Slavery International and European Center for Constitutional and Human Rights' position on import controls to address forced labour in supply chains](#)

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

D. कि न कारकों ने बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रभावित लोगों की स्थिति में सुधार के एक मजबूत उपाय के रूप में आयात प्रतिबंधों के सफल उपयोग में योगदान दिया है या कम किया है?

सीबीपी और सभी प्रासंगिक हितधारकों, विशेष रूप से श्रमिकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज और स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सलाहकारों के बीच सक्रिय जुड़ाव प्रभावित अधिकारधारकों के लिए सुधार संबंधी उपायों के प्रभावी प्रावधान में योगदान कर सकता है।

- 3.30 कुल मिलाकर, रिपोर्ट में शामिल केस स्टडीज के अध्ययन से पता चलता है कि बंधुआ मजदूरी से प्रभावी मुक्ति का दावा वही कंपनी या कर सकती हैं, जिन कंपनीयों को नागरिक समाज या स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सलाहकारों का समर्थन प्राप्त है। विशेष रूप से, जहां कि सी नागरिक समाज समूह या ट्रेड यूनियन द्वारा संशोधन या आयात प्रतिबंध को रद्द करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की जाती है या इन समूहों का समर्थन प्राप्त होता है, सीबीपी द्वारा प्रतिबंध को संशोधित करने या हटाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की संभावना थी।
- 3.31 नागरिक समाज और सीबीपी के बीच सक्रिय जुड़ाव यह सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकता है कि सीबीपी को कि सी कंपनी द्वारा अपने संचालन में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए एक एगए उपायों की जानकारी दी जाए। इसमें प्रभावित अधिकारधारकों के लिए एक एगए विशिष्ट उपाय भी शामिल कि ये जाने चाहिए। कुछ मामलों में, सीबीपी के याचिकाकर्ताओं ने उन उपायों को सूचीबद्ध किया है, जिनकी उन्हें कंपनीयों से अमल की उम्मीद है। अन्य मामलों में, नागरिक समाज समूहों ने आयात प्रतिबंधों के जवाब में कंपनीयों द्वारा लागू सुधारात्मक कार्रवाइयों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने के लिए सीबीपी को लिखा है। जुड़ाव के दोनों रूप सीबीपी को मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं ताकि यह मूल्यांकन करने में मदद मिल सके कि क्या कि सी कंपनी के पास बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के पर्याप्त साधन हैं। इनमें लोगों के लिए उपायों की स्थिति भी शामिल है। इसके बदले में, कंपनीयों द्वारा कि जाने वाले उपायों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।

व्यक्तिगत स्तर पर सुधारात्मक उपायों के प्रावधान के स्थान पर बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने से बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर श्रमिकों के लिए एक प्रभावी मददगार के रूप में टैरिफ अधिकारों की प्रभावशीलता में बाधा आती है।

- 3.32 कि सी विश्वोल्ड रि लीज ऑर्डर या निष्कर्षों को संशोधित या रद्द करने का फैसला करते समय सीबीपी प्रारंभिक रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11 संकेतकों को हटाने या कंपनी के संचालन में मौजूद रहने पर विचार करता है। श्रमिकों और प्रभावित अधिकारधारकों के लिए पर्याप्त उपचार का प्रावधान इस आकलन का हिस्सा है कि क्या जबरन श्रम के संकेतकों को प्रभावी ढंग से हटा दिया गया है, लेकिन यह सीबीपी का प्राथमिक विचार नहीं है।
- 3.33 व्यक्तिगत स्तर पर श्रमिकों के सुधार के प्रावधानों के स्थान पर सीबीपी का बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना, कंपनीयों द्वारा आयात प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है, आयात प्रतिबंधों पर कंपनी की प्रतिक्रिया संपूर्ण प्रणाली और नीति-स्तर के परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है। जहां व्यक्तिओं को उपचार प्रदान कि एगए हैं, ये भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति तक सीमित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। रिपोर्ट ने केवल एक मामले की पहचान की जिसे एक कंपनी सार्वजनिक रूप से उन श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध थी जो बंधुआ मजदूरी की स्थिति में थे।

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

3.34 जैसा कि एक हि तधारक ने महसूस कि या: "टैरि फ अधि नि यम की कमजोरी यह है कि कोई वि शि ष्ट उपाय प्रावधान नहीं है... मजबूर श्रम के संकेतक की अनुपस्थिति श्रमि कों के लिए उपाय के प्रावधान के बराबर नहीं है। हम पि छले वेतन, मुआवजे, भविष्य के दुरुपयोग को रोकने के लिए एसि स्टम, शि कायत तंत्र तक पहुंच, क्षमता निर्माण, जुड़ाव की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान देखना चाहते हैं, ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है।"

आयात प्रतिबंधों के जवाब में कंपनी के सुधारात्मक प्रयास आमतौर पर ऊपर से नीचे तक डिज़ाइन किए गए हैं, जोखिम-संचालित ऑडिट/अनुपालन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, और सीमित हि तधारक जुड़ाव के साथ - विशेष रूप से श्रमि कों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज के साथ। यह प्रणालीगत-स्तर के परिवर्तन करने के लिए कंपनी के सुधारात्मक प्रयासों की क्षमता में बाधा डालता है, और श्रमि कों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों के लिए उपचारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है।

3.35 रिपोर्ट में परीक्षण की गयी केस स्टडीज में कंपनियों ने समान तरीके से आयात प्रतिबंधों का जवाब दिया। कंपनी की श्रम प्रथाओं का आधारभूत मूल्यांकन करने और जबरन श्रम के संकेतकों की पहचान करने के लिए कंपनी ने पहले एक सामाजिक लेखा परीक्षक या बाहरी सलाहकार को नियुक्त किया। इसके बाद अपने सलाहकारों के परामर्श से, कंपनी जबरन श्रम के पहचाने गए संकेतकों को दूर करने के लिए एक सुधारात्मक कार्य योजना विकसित करेगी। सुधारात्मक कार्य योजना के पूरा होने पर, कंपनी सुधारात्मक कार्य योजना के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए एक और लेखापरीक्षा करेगी। कंपनी तब आयात प्रतिबंध को संशोधित करने या रद्द करने के लिए कंपनी की याचिका का समर्थन करने के लिए सीबीपी को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3.36 यह प्रवृत्ति, आंशिक रूप से, कंपनियों के लिए सीबीपी के मार्गदर्शन द्वारा संचालित होने की संभावना है - जो यह सुझाव देती है कि आयात प्रतिबंध को संशोधित करने या रद्द करने के लिए कंपनी की याचिकाओं को एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इस अनुपालन-संचालित सामाजिक अंकेक्षण दृष्टिकोण के साथ कंपनियों की परिचितता भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है।

3.37 रिपोर्ट बताती है कि आमतौर पर कंपनियों आयात प्रतिबंधों के जवाब में सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करते समय श्रमि कों, ट्रेड यूनियनों या विश्वसनीय कर्मचारी प्रतिनिधियों, नागरिक समाज और अन्य हि तधारकों को सार्थक रूप से शामिल नहीं करती हैं। हि तधारकों के अनुसार, आयात प्रतिबंधों के जवाब में विकसित सुधारात्मक कार्य योजनाएं आमतौर पर श्रमि कों और अन्य प्रभावित हि तधारकों के परामर्श के बजाय कंपनियों और उनके सलाहकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। कुछ मामलों में, कंपनियों ने आयात प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया पर सलाह देने के लिए स्वतंत्र समितियों का गठन किया है। हालांकि इन समितियों का गठन एक स्वागत योग्य और प्रगतिशील उपाय है, किन्तु ऐसी समितियों में आमतौर पर श्रमि कों, ट्रेड यूनियनों या अन्य विश्वसनीय कार्यकर्ता प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है।

3.38 मलेशिया में, कुछ कंपनियों ने श्रमि कों के साथ उनके द्वारा भुगतान की गई भर्ती शुल्क की राशि की जांच करने के लिए परामर्श किया, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उन्हें वादे के अनुसार भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है या नहीं। हालांकि, रिपोर्ट में ऐसे कि सी भी उदाहरण की पहचान नहीं की गई है जिसे कंपनियों ने प्रारंभिक परामर्श में श्रमि कों को प्रत्यक्ष रूप से उन उपायों पर उनके विचार जानने के लिए शामिल किया कि या हो, जो श्रमि क प्राप्त करना चाहते हैं।

56 Interview with Allison Gill, Forced Labor Director, Global Labor Justice-International Labor Rights Forum
 57 This basic pattern of behaviour can be observed, e.g., in the case studies of Malaysia's rubber glove and palm oil industries.
 58 CBP (March 2021) [Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview](#)
 59 Reuters (14 July 2021) [Experts quit Sime Darby Plantation panel over transparency concerns](#); FMT (14 July 2021) [Experts quit Sime Darby Plantation's human rights panel](#); The Business Times (15 July 2021) [Malaysia's Sime Darby Plantation scraps rights panel after resignations](#); Thomson Reuters Foundation (14 March 2021) [NGO exits Sime Darby Plantation rights panel over company's lawsuit](#) (Archived)

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

कंपनि याँ और सीबीपी सुधारात्मक उपायों के प्राथमिक सबूत के रूप में सोशल ऑडिट पर बहुत अधिक भरोसा करना जारी रखते हैं।

- 3.39 सोशल ऑडिट कंपनियों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं में बंधन आ मजदूरों से जुड़े जोखिमों की पहचान करने, रोकने, कम करने और उपाय करने में सहायक भूमिका निभा सकता है। हालांकि व्यापक शोध से पता चला है कि कंपनी द्वारा कमीशन किए गए सोशल ऑडिट की प्रभावी रूप से बंधुआ मजदूरी की पहचान करने में सीमित उपयोगिता है, और वास्तव में, मानवाधिकारों के जोखिम को बढ़ा सकता है। सोशल ऑडिट से स्वास्थ्य के स्वच्छ बिल प्राप्त करने वाली कंपनियों में कई उदाहरण हैं, जो अपनी मूल्य श्रृंखला में बंधुआ मजदूरी की उपस्थिति के कारण जल्द ही टैरिफ अधिनियम के तहत आयात प्रतिबंध का सामना करने वाली थीं।
- 3.40 रिपोर्ट में विचार की गई कई कंपनियों ने सोशल ऑडिट से गुजरती हैं, या आयात प्रतिबंध प्राप्त करने से पहले स्थिरता निष्कर्षों द्वारा प्रमाणित की गई थीं। कुछ मामलों में, इन सोशल ऑडिट ने आयात प्रतिबंध लागू होने से पहले बंधुआ मजदूरी के जोखिमों की पहचान की। हालांकि अन्य मामलों में, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
- 3.41 सोशल ऑडिटिंग के मिश्रित ट्रेंड रिपोर्ट के बावजूद, सीबीपी के मार्गदर्शन में कंपनियों को यह सत्यापित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है कि बंधुआ मजदूरों के संकेतकों को सुधारा गया है। इस प्रकार सीबीपी का मार्गदर्शन संभावित रूप से कंपनियों को सुधारात्मक कार्यक्रमों और सुधारात्मक कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सामाजिक लेखापरीक्षा के आधार पर हैं और यह बाद में कई केस स्टडीज में भी स्पष्ट रूप से सामने आई। बदले में ऊपर वर्णित सुधारात्मक उपायों की ऊपर से नीचे की प्रकृति को बनाए रखने का जोखिम भी सामने आता है।
- 3.42 सोशल ऑडिट पर जोर देने से श्रमिकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव के अन्य रूपों को छोड़कर यह प्रदर्शित करने का जोखिम भी है कि बंधुआ मजदूरों के संकेतकों में सुधार किया गया है। उदाहरण के लिए, बहु-हितधारक प्रक्रियाओं, लागू करने योग्य ब्रांड समझौतों, या कार्यकर्ता के नेतृत्व वाले सुधारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से।
- 3.43 ऐसे संकेत हैं कि सीबीपी अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए, सीबीपी ने कंपनी द्वारा कराए गए कमर्शियल सोशल ऑडिट के बजाय नागरिक समाज समूहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आयात प्रतिबंध हटा दिया है। यह नाची एपेरेल्स और अन्नपूर्णा कार्पेट से जुड़े मामलों में स्पष्ट था। इन मामलों में, सीबीपी ने श्रमिकों के साक्षात्कार और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ नागरिक समाज संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इन कंपनियों पर से आयात प्रतिबंध हटा लिया। इसलिए ये मामले बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के प्रयासों को दर्शाने के लिए कंपनी द्वारा कराए जाने वाले कमर्शियल सोशल ऑडिट का विकल्प नजर आते हैं।

सुधार के उपायों के आसपास पारदर्शिता और प्रभावी संचार की कमी है। यह नागरिक समाज की कंपनियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता में बाधा डालता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपायों तक प्रभावी पहुंच प्रदान की जाए।

- 60 See, e.g., Human Rights Watch (November 2022) *Obsessed with Audit Tools, Missing the Goal*; European Center for Constitutional and Human Rights, Brot für die Welt, MISEREOR (2021) *Human rights fitness of the auditing and certification industry?*; Transparentem (2021) *Hidden Harm: Audit Deception in Apparel Supply Chains and the Urgent Case for Reform*; Clean Clothes Campaign (2019) *Fig Leaf for Fashion. How social auditing protects brands and fails workers*; SOMO (2022) *A piece, not a proxy: The European Commission's dangerous overreliance on industry schemes, multi-stakeholder initiatives, and third-party auditing in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive*
- 61 See, e.g., The Edge Markets (2 November 2020) *Top Glove downgraded from A to D in social compliance audit — report*; Reuters (19 May 2021) *'Slavery' found at a Malaysian glove factory. Why didn't the auditor see it?*; Human Rights Watch (November 2022) *Obsessed with Audit Tools, Missing the Goal*
- 62 CBP (March 2021) *Factsheet: WRO Modification/Revocation Process Overview*

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

- 3.44 हि तधारक बताते हैं कि सीबीपी ने हाल के वर्षों में अपने संचार, खुलेपन और पारदर्शिता के स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि, सुधार की प्रक्रिया काफी हद तक अपारदर्शी बनी हुई है। उदाहरण के लिए, संक्षिप्त प्रेस विज्ञापनों के अलावा, सीबीपी विदहोल्डरि लीज ऑर्डर और निष्कर्षों को संशोधित करने या रद्द करने के अपने निर्णयों के विस्तृत और विशिष्ट कारणों का प्रचार नहीं करता है।
- 3.45 इसके अलावा, सीबीपी के लिए कंपनीयों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने विदहोल्डरि लीज ऑर्डर या निष्कर्षों के जवाब में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को सुधारने या बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की गवाही देती ऑडिट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को प्रकाशित करने लिए क्या कार्रवाई की है। जबकि कुछ कंपनियों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट और सुधारात्मक कार्य योजनाओं के निष्कर्षों को सार्वजनिक करके सकारात्मक कदम उठाए हैं। बहुतों ने ऐसा भी नहीं किया है।
- 3.46 कंपनियों और सीबीपी से पारदर्शिता की यह कमी, कंपनियों के उपचारात्मक प्रयासों की पर्याप्तता की प्रभावी निगरानी करने के लिए नागरिक समाज की क्षमता में बाधा डालती है। यह विदहोल्डरि लीज ऑर्डर और निष्कर्षों को संशोधित करने या रद्द करने के अपने निर्णयों के लिए सीबीपी को जिम्मेदार ठहराने की नागरिक समाज की क्षमता में भी बाधा डालता है।
- 3.47 कंपनियों या सीबीपी से अधिक पारदर्शिता का भी लाभ उठा सकती हैं। हि तधारकों के अनुसार, जब कंपनियों पर आयात प्रतिबंध लगाया जाता है तो उन्हें अक्सर सीबीपी द्वारा सूचित नहीं किया जाता है, और सीबीपी कंपनियों को विस्तृत और विशिष्ट कारण नहीं बताता प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्णय क्यों लिया है। हालांकि बड़ी कंपनियों को सीबीपी के प्रवर्तन निर्णयों के बारे में पता होने की संभावना है, किन्तु छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि किसी कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह आयात प्रतिबंध के अधीन है, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह कंपनी बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई करेगी। इसलिए यह प्रभावित अधिकारधारकों के लिए सुधारात्मक उपायों के प्रावधान में तब तक की देरी का कारण बन सकता है, जब तक कंपनी को आयात प्रतिबंध की सूचना नहीं मिल जाती।



63 Specifically, companies reported that while CBP discloses the indicators of forced labour it identified, CBP does not disclose the basis for the identification of those indicators. For example, CBP might state that it identified indicators of debt bondage in a company's operations, but might not say specifically how that debt bondage manifests, or in what sites or locations the indicators of debt bondage were found to be present.

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज के लि ए

- 4.1 श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, ट्रेड यूनि यनों और नागरि क समाज समूहों के लि ए, बंधुआ मजदूरी की स्थि ति में फंसे लोगों तक सुधार के लाभ पहुंचाना सुनि श्चि त करने के लि ए टैरि फ अधि नि यम तंत्र का अधि क प्रभावी ढंग से उपयोग करना जरूरी है। इसके लि ए नि म्नि लि खि त कदम उठाए जा सकते हैं।

आयात प्रति बंध से जुड़ी याचि का सीबीपी में जमा करने पर वि चार करते समय श्रमि कों और अधि कार धारकों के साथ सार्थक रूप से परामर्श करें।

- 4.2 सीबीपी को याचि का प्रस्तुत करने से पहले श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ सार्थक परामर्श आवश्यक है ताकि यह सुनि श्चि त कि या जा सके कि संभावि त आयात प्रति बंध का अनुरोध श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के हि तों के अनुरूप है। श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों के साथ पूर्व परामर्श यह पहचानने के लि ए भी महत्वपूर्ण है कि अधि कार धारक बंधुआ मजदूरी के कौन से उपायों से जुड़ना चाहते हैं।

सीबीपी याचि काओं में उन उपायों पर वि शि ष्ट सि फारि शें शामि ल होनी चाहि ए जो श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों को प्रदान की जानी चाहि ए।

- 4.3 आयात प्रति बंधों की याचि काओं में, जहां संभव हो, बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को दूर करने के लि ए संभावि त प्रयासों को भी संबन्धि त कंपनी के लि ए सि फारि शों में शामि ल कि या जाना चाबि ए। इन सुधारों में प्रभावि त श्रमि कों और अधि कार धारकों के लि ए उपचार का प्रावधान शामि ल होना चाहि ए।
- 4.4 यूएनजीपी के अनुरूप, इन उपायों में वि तीय मुआवजे का प्रावधान, भर्ती शुल्क और खर्चों की प्रति पूर्ति (जहां प्रासंगि क हो), शारीरि क या मनोवैज्ञानि क पुनर्वास, माफी, गैर-दोहराव की गारंटी, और नुकसान के अपराधि यों के लि ए कानूनी जवाबदेही शामि ल हो सकती है। इन उपायों को श्रमि कों और उनके वि श्वसनीय प्रति नि धि यों और अन्य अधि कार धारकों के परामर्श से वि कसि त कि या जाना चाहि ए ताकि यह सुनि श्चि त कि या जा सके कि प्रस्तावि त सुधार श्रमि कों और अधि कार धारकों की जरूरतों और चि त्ताओं के अनुरूप हैं और उनके द्वारा अनुभू व कि ए गए नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकते हैं।
- 4.5 याचि का में सुधार की दृष्टि से वि शि ष्ट सि फारि शों को शामि ल करने से कंपनी के साथ इसके बाद के जुड़ाव में सीबीपी को मार्गदर्शन करने में मदद मि ल सकती है, और कंपनी की सुधारात्मक कार्य योजना की पर्या प्तता का आकलन करने में मदद मि ल सकती है। सीबीपी को यह बताना वि शेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता और अधि कार धारक क्या सुधार देखना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि सीबीपी के पास प्रत्येक कंपनी, उद्योग, या भौगोलि क क्षेत्र का उसी तरह गहन ज्ञान और वि शेषज्ञता होने की संभावना नहीं है, जि स तरह स्वयं श्रमि कों और अधि कार धारकों के पास होगी। इसलि ए श्रमि क और अधि कार धारक स्वयं यह आकलन करने के लि ए सबसे अच्छी स्थि ति में हैं कि क्या सुधार कि ये जाने चाहि ए, जि ससे उन्हें बंधुआ मजदूरी के अधीन होने के परि णामस्वरूप हुए नुकसान से पूरी तरह बाहर नि काला जा सके।

सुधार प्रक्रि या के दौरान सीबीपी के साथ सक्रि य रूप से जुड़ें

64 If the Petition relates to an entire industry, rather than an individual company, the Petition should specify what Remediation should be undertaken by individual companies to demonstrate that their products are not made with, or using, forced labour. For detailed guidance on how to draft a Petition to CBP, see: Human Trafficking Legal Center (2020) [Importing Freedom: Using the US Tariff Act to Combat Forced Labour in Supply Chains](#)

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

- 4.6 जहां जब एक कंपनी आयात प्रतिबंध के जवाब में बंधुआ मजदूरी के सुधारात्मक संकेतकों के लिए कदम उठाती है, श्रमिकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों को उन प्रयासों का गंभीर रूप से आकलन करना चाहिए और सीबीपी को उनके आकलन की सूचना देनी चाहिए।
- 4.7 जहां संभव हो, इन आकलनों को श्रमिकों, श्रमिकों के विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए ताकि कंपनी द्वारा वादा किए गए या प्रदान किए गए सुधारों (यदि कोई हो) की पर्याप्तता पर श्रमिकों के विचारों को समझा जा सके।
- 4.8 यदि ऐसा मूल्यांकन संभव नहीं है (उदाहरण के लिए, क्योंकि कंपनी अपने सुधारात्मक प्रयासों के बारे में पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है, श्रमिकों तक पहुंच संभव नहीं है, या कंपनी श्रमिकों, उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, या नागरिक समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से जुड़ने को तैयार नहीं है) तो पारदर्शिता और प्रकटीकरण की कमी को सीबीपी के साथ उठाया जाना चाहिए।

सीबीपी के लिए

- 4.9 रिपोर्ट का फोकस टैरिफ एक्ट की आयात प्रतिबंध प्रणाली के संदर्भ में उपायों के प्रावधान पर है, न कि सीबीपी के आंतरिक तंत्र और प्रक्रियाओं पर। हालांकि, रिपोर्ट ने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जहां सीबीपी के दृष्टिकोण में सुधार किया जा सकता है ताकि बंधुआ मजदूरी और अन्य हितधारकों की स्थिति में लोगों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। यहां यह तथ्य स्वीकार्य है कि उपाय का प्रावधान सीबीपी के विशिष्ट जनादेश के भीतर नहीं है, न ही टैरिफ एक्ट की कार्यप्रणाली इसका विशिष्ट उद्देश्य है।

बंधुआ मजदूरी संकेतकों के सुधार पर श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधि कारधारकों की समस्याओं के समाधान के प्रावधान पर अधिक जोर देने के साथ विस्तृत मार्गदर्शन प्रकाशित करें।

- 4.10 बंधुआ मजदूरी संकेतकों के सुधार पर श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधि कारधारकों की समस्याओं के समाधान के प्रावधान पर अधिक जोर देने के साथ विस्तृत मार्गदर्शन प्रकाशित करें।
- बंधुआ मजदूरी के संकेतकों को सुधारे जाने या हटाए जाने का आकलन करते समय सीबीपी द्वारा लागू साक्ष्य मानकों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, सीबीपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कंपनी को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने संचालन में बंधुआ मजदूरी के जोखिम को पहचानने और कम करने के लिए तंत्र स्थापित किया है, या उन्हें यह प्रदर्शित करना चाहिए कि अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं है।
 - विदहोल्ड रिजिस्टर या सूचना में संशोधन या वापसी की शर्त के रूप में कंपनी को प्रदर्शित करना होगा:
 - श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधि कारधारकों को पर्याप्त उपचार प्रदान किया (न केवल वादा किया गया);
 - कर्मचारियों और अन्य प्रभावित अधि कारधारकों, श्रमिकों के विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों और/या अन्य प्रासंगिक नागरिक समाज समूहों के साथ कंपनी के सुधार संबंधी प्रयासों के नियोजन, विकास और कार्यान्वयन में सार्थक रूप से संलग्नता रही; और

65 Compare, e.g., the language used in CBP's press release on CBP 3 June 2020 ([CBP Modifies Withhold Release Order on Imports of Tobacco from Malawi](#)) where CBP refers to a company's "efforts to minimize the risks of forced labor from its supply chain", and its statement on 3 February 2023 CBP ([CBP Modifies Finding on Sime Darby Berhad in Malaysia](#)), where it refers to evidence that the company concerned "no longer produces...products using forced labour" (emphasis added).

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

○ सुधार की समग्र प्रक्रिया के संबंध में खुला और पारदर्शी रहा है (उदाहरण के लिए, हि तधारकों के साथ सार्थक जुड़ाव के माध्यम से, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सुधारात्मक कार्य योजनाओं के प्रकाशन से)।

- स्पष्ट करें कि सीबीपी उद्योगों या भौगोलिक क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी के संकेतकों के सुधार का आकलन कैसे करेगा जहां बंधुआ मजदूरी के व्यापक और प्रणालीगत जोखिम हैं जो एक व्यक्तिगत कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यदि सीबीपी इन संदर्भों में एक अलग मानक लागू करेगा, तो सीबीपी को निर्दिष्ट करना चाहिए कि यह कौन सा मानक लागू होगा, और कि न परिस्थितियों में।

सीबीपी की निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान कंपनी द्वारा अधिकृत सोशल ऑडिट पर निर्भरता कम करें।

4.11 कंपनीयों द्वारा प्रदान की गई सोशल ऑडिट रिपोर्ट को सीबीपी द्वारा विचार किए गए कई डेटा बिंदुओं में से एक होना चाहिए। विद्वहोल्डर लीज ऑर्डर या निष्कर्षों को संशोधित करने या रद्द करने का निर्णय लेते समय, सीबीपी को विभिन्न सूचना स्रोतों पर विचार करना चाहिए जिन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तुलना में यदि अधिक नहीं, तो कम से कम समान महत्व तो दिया जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी में श्रमिकों के विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों और अन्य नागरिक समाज संगठनों से सीधे कार्यकर्ता की गवाही और प्रस्तुतियाँ शामिल हो सकती हैं।

4.12 विशेष रूप से, विद्वहोल्डर लीज ऑर्डर या निष्कर्षों को संशोधित करने या रद्द करने के लिए कंपनीयों द्वारा याचिकाओं पर विचार करते समय सीबीपी को:

- कंपनीयों को बंधुआ मजदूरी से जुड़े संकेतकों में सुधार के साक्ष्य के विशिष्ट स्रोत प्रदान करने की आवश्यकता है (यानी, केवल सोशल ऑडिट रिपोर्ट न हो।) इसमें श्रमिकों या उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष साक्ष्य और गवाही, या नागरिक समाज संगठनों या ट्रेड यूनियनों की रिपोर्ट को शामिल किया जा सकता है।
- कंपनीयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसे सीबीपी सोशल ऑडिट की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता का आकलन करेगा। उदाहरण के लिए इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लेखापरीक्षक के चयन पर मार्गदर्शन, लेखापरीक्षा पद्धति और निष्कर्षों की पारदर्शिता और प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकताएं, और श्रमिकों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों के साथ सार्थक जुड़ाव का प्रमाण शामिल हैं।

हि तधारक जुड़ाव और संवाद में सुधार करें

4.13 When CBP imposes a WRO or Finding on a company, it should notify that company. CBP should also provide the company with its detailed and specific reasons why it has taken enforcement action. This should include not only a list of the indicators of forced labour identified by CBP, but also the specific factors that give rise to that indicator (in a way that protects the confidentiality of sources). जब सीबीपी किसी कंपनी पर विद्वहोल्डर लीज ऑर्डर या निष्कर्षों के अनुरूप कार्रवाई करत है, तो उसे उस कंपनी को सूचित करना चाहिए। सीबीपी को कंपनी को इसके विस्तृत और विशिष्ट कारण भी बताने चाहिए कि उसने प्रवर्तन कार्रवाई क्यों की है। इसमें न केवल सीबीपी द्वारा पहचाने गए बंधुआ मजदूरी के संकेतकों की एक सूची शामिल होनी चाहिए, बल्कि उन विशिष्ट कारणों को भी शामिल करना चाहिए जो उस सूचक को जन्म देते हैं (एक तरह से जो स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करते हैं)।

4.14 सीबीपी को सुधार प्रक्रिया के दौरान हि तधारकों के साथ अपने सक्रिय जुड़ाव को भी व्यापक और बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से, जब सीबीपी किसी कंपनी द्वारा आयात प्रतिबंध को संशोधित करने या रद्द करने के आवेदन पर विचार कर रहा है, तो सीबीपी को कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, श्रमिकों के विश्वसनीय प्रतिनिधियों और अन्य नागरिक समाज समूहों के साथ कंपनी के उपचार की पर्याप्तता पर उनके विचार जानने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए।

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

श्रमि कों और अन्य प्रभावि त अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल प्रभावों को रोकने या कम करने के लि ए आवश्यक होने पर अधि क लचीले प्रवर्तन वि कल्पों पर वि चार करे

- 4.15 It may be beneficial for CBP to have a more flexible range of options for the enforcement of import bans. Greater flexibility in enforcement options can help to avoid or mitigate potential adverse consequences for workers and other rights holders that may potentially arise from the immediate imposition of import bans. For example, in 2020 International Rights Advocates and the Corporate Accountability Lab submitted a Petition to CBP calling for an import ban of cocoa products from Cote D'Ivoire. In the Petition, the petitioners called on CBP to compel US cocoa importers to submit satisfactory evidence that shipments of cocoa imported by them were not made with or using forced child labour within 180 days. सीबीपी के लि ए आयात प्रति बंधों को लागू करने के लि ए वि कल्पों की अधि क लचीली रेंज होना फायदेमंद हो सकता है। प्रवर्तन वि कल्पों में अधि क लचीलेपन से श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल परि णामों से बचने या कम करने में मदद मि ल सकती है जो संभावि त रूप से आयात प्रति बंधों के तत्काल लागू होने से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लि ए, 2020 में इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स और कॉरपोरेट एकाउंटेबि लि टी लैब ने कोटे डी आइवर से कोको उत्पादों के आयात पर प्रति बंध लगाने के लि ए सीबीपी को एक याचि का प्रस्तुत की। याचि का में, याचि काकर्ता ओं ने सीबीपी से अमेरि की कोको आयातकों को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लि ए मजबूर करने के लि ए कहा कि उनके द्वारा आयात कि ए गए कोको का शि पमेंट 180 दि नों के भीतर या जबरन बाल श्रम के साथ नहीं कि या गया था।
- 4.16 It may be beneficial for CBP to have a more flexible range of options for the enforcement of import bans. Greater flexibility in enforcement options can help to avoid or mitigate potential adverse consequences for workers and other rights holders that may potentially arise from the immediate imposition of import bans. For example, in 2020 International Rights Advocates and the Corporate Accountability Lab submitted a Petition to CBP calling for an import ban of cocoa products from Cote D'Ivoire. In the Petition, the petitioners called on CBP to compel US cocoa importers to submit satisfactory evidence that shipments of cocoa imported by them were not made with or using forced child labour within 180 days. सीबीपी के लि ए आयात प्रति बंधों को लागू करने के लि ए वि कल्पों की अधि क लचीली रेंज होना फायदेमंद हो सकता है। प्रवर्तन वि कल्पों में अधि क लचीलेपन से श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों के लि ए संभावि त प्रति कूल परि णामों से बचने या कम करने में मदद मि ल सकती है जो संभावि त रूप से आयात प्रति बंधों के तत्काल लागू होने से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लि ए, 2020 में इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स और कॉरपोरेट एकाउंटेबि लि टी लैब ने कोटे डी आइवर से कोको उत्पादों के आयात पर प्रति बंध लगाने के लि ए सीबीपी को एक याचि का प्रस्तुत की। याचि का में, याचि काकर्ता ओं ने सीबीपी से अमेरि की कोको आयातकों को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लि ए मजबूर करने के लि ए कहा कि उनके द्वारा आयात कि ए गए कोको का शि पमेंट 180 दि नों के भीतर या जबरन बाल श्रम के साथ नहीं कि या गया था।
- 4.17 महत्वपूर्ण रूप से, सीबीपी को अधि क लचीले प्रवर्तन वि कल्पों को तभी अपनाना चाहि ए जब श्रमि कों और अन्य अधि कार धारकों की सुरक्षा के लि ए आवश्यक हो। यह नि र्णय लेने में सीबीपी को श्रमि कों, श्रमि कों के वि श्वसनीय प्रति नि धि यों, या ट्रेड यूनि यनों के कि सी भी नि वेदन पर ध्यान देना चाहि ए।

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

आयात प्रतिबंधों से प्रभावित न्यायालयों में सरकारों के लिए

बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को समझते हुए आयात प्रतिबंधों के जवाब में बंधुआ मजदूरी के लिए हुए उपायों का समर्थन करें

- 4.18 आयात प्रतिबंधों से प्रभावित न्यायक्षेत्र की सरकारों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लिए कानूनी और नीतिगत सुधारों को लागू करने के साथ-साथ कानूनी रूप से अपने अधिकांश क्षेत्र के तहत कंपनियों की जांच करके कंपनियों के प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। इनमें वे कंपनियां भी होंगी जो बंधुआ मजदूरी व अन्य मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेह हैं।
- 4.19 मानव अधिकारों की अनिवार्यता से परे, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बंधुआ मजदूरी के पीछे के मूल कारणों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों को दूर करने के लिए कार्रवाई करके, सरकार प्रमुख निर्यात उद्योगों को भविष्य के आयात प्रतिबंधों के जोखिम से बचाने में मदद कर सकती है। सरकार बदले में नौकरियों और अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में मदद करती है। ऐसे सुधारों में शामिल हो सकते हैं:
- Ensuring that forced labour is effectively criminalised under domestic law, and that the legal definition of forced labour is aligned with the 1930 ILO Forced Labour Convention. यह सुनिश्चित करना कि बंधुआ मजदूरी को घरेलू कानून के तहत प्रभावी रूप से अपराधीकृत किया जाता है, और यह कि बंधुआ मजदूरी की कानूनी परिभाषा 1930 के अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) के बंधुआ मजदूरी सम्मेलन की मंशा के अनुरूप है।
 - प्रवासी और गैर-प्रवासी श्रमिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देना - जिसे संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी, मजदूरी और काम करने की स्थिति शामिल है।
 - श्रम निरीक्षकों को पर्याप्त रूप से संसाधन देना, और श्रम कानूनों, नीतियों और विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।
 - यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम और प्रवासन नीतियों में जबरन श्रम, तस्करी और शोषण के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय हैं (उदाहरण के लिए, भर्ती शुल्क लेने पर प्रतिबंध, कर्मचारी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित रोजगार अनुबंध के प्रावधान की आवश्यकताएं, निर्यातकों द्वारा पासपोर्ट और दस्तावेज प्रतिधारण पर रोक लगाना, और श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से निर्यात बदलने की अनुमति देना)।
 - यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों की प्रभावी शिकायत तंत्र (राज्य-आधारित, गैर-राज्य आधारित, न्यायिक और गैर-न्यायिक प्रणालियों सहित) तक पहुंच हो।

निजी क्षेत्र के लिए

सुधार प्रक्रियाओं के नियोजन, विकास और कार्यान्वयन में श्रमिकों और नागरिक समाज के साथ सार्थक रूप से संलग्न हों

- 4.20 सुधार के लिए कंपनियों के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए श्रमिकों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्थक रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों और उनके विश्वसनीय प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज और अन्य संबंधित हितधारकों को सुधार प्रक्रियाओं के नियोजन, विकास, कार्यान्वयन और निगरानी में सार्थक रूप से परामर्श दिया जाए।

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

4.21 डि डिं गीगलु समझौते जैसे ही बहु-हि तधारक पहलें इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि लि गं और जाति -आधारित त भेदभाव जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों और एक तरह से गहन रूप से उलझे हुए और जटिल मुद्दों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण को कैसे लागू किया जा सकता है जो सीधे तौर पर कर्मचारियों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी है। वे कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों के मुद्दों के समाधान के लिए ए कॉर्पोरेट प्रशासन परिवर्तन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संघ की स्वतंत्रता की गारंटी, और शि कायत तंत्र तक बेहतर पहुंच के संयोजन के माध्यम से बहु-स्तरीय दृष्टिकोण का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।

सुधार के लिए एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं, न कि अनुपालन-आधारित दृष्टिकोण

4.22 कंपनियों को लंबे समय में जोखिम और अनुपालन-संचालित मानसिकता से दूर जाकर और सुधार के लिए कर्मचारियों को कंपनी के दृष्टिकोण के केंद्र में रखने वाला मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने से लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, कंपनियों को अधिकारधारकों को होने वाले नुकसान की पहचान करने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ऐसे नुकसान के कारण, प्रभावित लोगों को उस प्रभाव से बाहर निकालने के तरीके और उस नुकसान की गैर-दोहराव की गारंटी के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

4.23 इस तरह के दृष्टिकोण से एक समग्र और दीर्घकालिक समाधान प्राप्त होने की अधिक संभावना है। इससे भविष्य में बंधुआ मजदूरी के जोखिमों को काफी हद तक कम करने की संभावना है। जो कंपनियाँ उपायों के लिए 'टिक बॉक्स' या अनुपालन-संचालित दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प चुनती हैं, उन्हें यह पता चल सकता है कि वे बंधुआ मजदूरी के मूल कारणों की ठीक से पहचान करने और उनका समाधान करने में विफल रही हैं, जिससे उन्हें भविष्य में प्रवर्तन कार्रवाई के लिए उजागर किया जा सके।

सुधार प्रक्रिया में अपस्ट्रीम कंपनियों को शामिल करें

4.24 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, खरीदारों और ब्रांडों को अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए उपचारात्मक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के आपूर्तिकर्ता को आयात प्रतिबंध प्राप्त होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को तुरंत 'काटने और चलाने' से बचना चाहिए - विशेष रूप से यदि आपूर्तिकर्ता सुधार करने के लिए तैयार है। इसके बजाय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को अपने उत्तोलन का उपयोग करना चाहिए और अपने उपचारात्मक प्रयासों में आपूर्तिकर्ता की मदद करने के लिए अपने संसाधनों की पेशकश करनी चाहिए।

4.25 यदि कोई खरीदार आयात प्रतिबंध के कारण आपूर्तिकर्ता के साथ अपने संबंध समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जिम्मेदारी से और इस तरह से अलग हो जाए जो श्रमिकों और अधिकारधारकों के लिए संभावित प्रतिफल प्रभावों को कम करता हो।

For the European Commission

4.26 सितंबर 2022 में, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ (ईयू) के बाजार में बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों को प्रतिबंधित करने के लिए एक विनियमन प्रस्ताव प्रकाशित किया। हालांकि प्रस्तावित विनियमन सीधे तौर पर टैरिफ अधिकारों पर आधारित नहीं है, किन्तु रिपोर्ट के निष्कर्ष यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं के लिए सीधे प्रासंगिक हैं क्योंकि वे प्रस्तावित विनियमन का पथ प्रशस्त करते हैं।

4.27 प्रस्तावित संस्तुतियों के लिए संस्तुतियों का एक विशद समूह यहां उपलब्ध है। किन्तु संक्षेप में प्रस्तावित विनियमन कहता है:

4. प्रमुख अनुशंसाओं का सारांश

- A. यह सुनिश्चित करें कि सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज सहित हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श में संलग्न हों - न कि केवल आर्थिक संचालकों के साथ।
- B. कंपनी द्वारा कराए गए 'सोशल ऑडिट' पर प्राथमिक सबूत के रूप में स्वीकार्यता की निम्नता को कम करें।
- C. कंपनियों के लिए कि सी भी प्रकार के 'सुरक्षित बंदरगाह' की पेशकश सिर्फ उनकी उचित परिश्रम प्रक्रियाओं की स्पष्ट पर्याप्तता के आधार पर न की जाए।
- D. सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों और अन्य प्रभावित अधिकारधारकों के लिए उपायों तक पहुंच (जैसा व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिभाषित है) को प्रवर्तन उपायों को हटाने की शर्त के रूप में प्रदान किया गया है।
- E. केवल उन आर्थिक संचालकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए जो बंधुआ मजदूरी के प्रवर्तक हैं, बल्कि इस आधार पर जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि आर्थिक संचालक किस हद तक बंधुआ मजदूरी का कारण बने हैं, उसमें योगदान दिया है या उसका लाभ उठाया है।